



हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

ओलंपस हाईस्कूल के छात्रों ने किया चिड़ियाघर का भ्रमण (संवाददाता) देहरादून। ओलंपस हाई स्कूल के प्रि प्राइमरी सेक्शन ने आज अपने वार्षिक भ्रमण के हिस्से के रूप में देहरादून चिड़ियाघर और फन एन फूड किंगडम का दौरा किया।

छोटे ओलंपियनों ने सवारियों का आनंद लिया, गाने गाये और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक लंच का आनंद लिया। देहरादून चिड़ियाघर की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई जानवरों के बारे में सीखा। वे मछली, जानवरों, पक्षियों और कैक्टस के बगीचे को देखकर रोमांचित हो उठे।

‘वरली आर्ट पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला’ का आयोजन (संवाददाता) देहरादून। यूसर्क एवं साहस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज दिनांक 18 दिसम्बर 2019 को उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क) के सभागार में यूसर्क के दिव्यांग केन्द्र के अन्तर्गत ‘वरली आर्ट पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला’ का आयोजन किया गया। यूसर्क के निदेशक प्रो दुर्गेश पंत ने बताया कि यूसर्क निरन्तर दिव्यांग जनों के उत्थान एवं सशक्तीकरण हेतु पूरे प्रदेश में कार्य कर रहा है।

आईटीआई म्युचुअल फंड ने आईटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च किया (संवाददाता) देहरादून। आईटीआई म्युचुअल फंड का लक्ष्य सही समय पर निवेशकों को सही उत्पाद की पेशकश करना और एक अद्वितीय निवेश दर्शन पर ध्यान केंद्रित करके एसेट मैनेजमेंट स्पेस में एक नया प्रतिमान लाना है। फंड हाउस का उद्देश्य हमारे सभी निवेशकों के लिए निरंतर और बेहतर निवेश अनुभव उत्पन्न करना है। आईटीआई म्युचुअल फंड ने अपने 6 वें फंड आईटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ‘को लॉन्च करने की घोषणा की है।

लोकतंत्र के प्रति देशवासियों का विश्वास बढ़ा: लोस अध्यक्ष

शुभारंभ

संवाददाता

देहरादून। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने बुधवार को प्रेमनगर स्थित स्थानीय होटल में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों के 79वें वार्षिक सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों का उत्तराखण्ड में पहला सम्मेलन है। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि गंगा यमुना के उदगम की धरती देवभूमि उत्तराखण्ड में आयोजित इस सम्मेलन में लोकतंत्र की मजबूती के लिए व्यापक स्तर पर चर्चा होगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होते हैं।

लोकतंत्र के प्रति देशवासियों का विश्वास बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप 17वें लोक सभा चुनाव में 67.40 प्रतिशत मतदान

लोस अध्यक्ष व सीएम ने किया विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों के 79वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ



विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों के 79वें वार्षिक सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करते हुए।

हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि संसदीय सत्र में सभी सदस्यों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिले। 17वीं लोक सभा के गठन के बाद पहला सत्र 37 दिन तक चला, जिसमें 35 विधेयक पारित हुए। इस दौरान एक दिन भी संसद की कार्यवाही स्थगित नहीं हुई। प्रश्नकाल एवं

शून्यकाल में सदस्यों के अधिकतम प्रश्नों को रखने का मौका दिया। पहली बार निर्वाचित होने वाले सदस्यों को सदन में अधिक से अधिक बोलने के लिए आग्रह किया। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है कि दून में आयोजित इस सम्मेलन में विधानसभा एवं लोक सभा के मन्दिरो को कैसे और अधिक मजबूत

किया जा सकता है, इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि के अन्दर जो दो दिवसीय चर्चा होगी, इसके आने वाले समय में अनेक सकारात्मक परिणाम होंगे। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब उत्तराखण्ड को इस तरह के आयोजन की मेजबानी मिली है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र में आप जैसे लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सदन का अध्यक्ष एक अभिभावक की तरह होता है। हम उत्तराखण्ड में ई-कैबिनेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि राज्य में जल्द ही ई-विधानसभा की शुरुआत की जाय।

विस अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों को सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखण्ड के धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान पर विस्तार से जानकारी दी।

उत्तराखण्ड के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे ये सभी योजनाएं: सीएम

(संवाददाता) देहरादून। केंद्र सरकार ने जमरानी बांध बहुदेशीय परियोजना के लिए 2584 करोड़ रूपए, टिहरी लेक डेवलपमेंट के लिए 1200 करोड़ रूपए और देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए 1400 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ‘मैं प्रधानमंत्री जी का उत्तराखण्ड की जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वे हमेशा उत्तराखण्ड की चिंता करते हैं। राज्य सरकार उनके विजन के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए तत्पर है। पहले ही ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है।

केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से ये सभी योजनाएं उत्तराखण्ड के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बहुदेशीय परियोजना तराई भाबर की लाइफ-लाइन है। अब इस महत्वपूर्ण परियोजना के काम में और तेजी आए, दशकों से लटकी पड़ी जमरानी बांध परियोजना को हकीकत बनाने के लिए हमारी सरकार ने गम्भीरता से कोशिश की।

उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर मोर्चा ने किया तहसील कार्यालय में प्रदर्शन, घेराव

(संवाददाता) विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण आदि मामलों ने उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना कराये जाने एवं सर्वोच्च न्यायालय में योजित एसएलपी वापस लिये जाने को लेकर मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से इस संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पर दिनांक 01.02.2019 को रोक लगा दी गयी है तथा नोटिस जारी किये गये हैं।

‘इण्डस्ट्रीज को म्युचुअल एंड प्लान बनाने की दी गई नसीहत’

बैठक

■ 17 जनवरी को आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल तैयारी हेतु बैठक आयोजित

देहरादून। संवाददाता

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल और आईआरएस विशेषज्ञ राज्य आपदा प्रबन्धन बी.बी गणनायक की संयुक्त अध्यक्षता में जनपद आपदा कन्ट्रोलरूम में कैमिकल डिजास्टर की मॉक एकसरसाइज के सम्बन्ध 1 में राज्य आपदा प्रबन्धन, जनपद आपदा प्रबन्धन और औद्योगिक



मॉक ड्रिल तैयारी को लेकर बैठक लेते एडीएम।

संगठनों के पदाधिकारियों के साथ आगामी 17 जनवरी को आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल तैयारी हेतु बैठक आयोजित की गयी।

‘इण्डस्ट्रीज को म्युचुअल एंड प्लान बनाने की दी गई नसीहत’ बैठक

में राज्य आईआरएस विशेषज्ञ बीबी गणनायक द्वारा औद्योगिक पदाधिकारियों को आगामी 17 जनवरी 2020 को होने वाले मॉक एकसरसाइज की बेहतर तैयारी और उद्योगों में घटने वाली

कैमिकल अथवा अन्य प्रकार की आपदा से निपटने हेतु म्युचुअल एंड प्लान बनाने के निर्देश दिये।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल ने आपदा प्रबन्धन अधिकारी को सभी इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों को उनके स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने, मानवीय तथा सभी प्रकार के संसाधन आदि का विवरण प्राप्त करें और अपने स्तर पर भी ‘इण्डस्ट्रियल रिस्क एसेसमेंट’ का प्लान तैयार करते हुए एडवाइजरी जारी करें। साथ ही हर 6 माह में नोडल अधिकारियों के विवरण को अपडेट करते रहने के निर्देश दिये।

In a Digital World Why To wait for a Howker

Visit Us at <http://app.page3news.co.in>

Supporting Devices

All Apple Touch Phones & Tablets
All Android Touch Phones & Tablets
All Window & BlackBerry Touch Phones 10+



Read News
Watch News Channel

Scan This Code



बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

(संवाददाता) देहरादून। प्याज सहित सब्जियों एवं अनारजों के बढ़ते दामों तथा मंहगाई को लेकर महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा के नेतृत्व में तहसील स्थित छोटी सब्जी मण्डी में विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर लालचन्द शर्मा ने कहा कि भाजपा के शासन में मंहगाई अपने चरम पर है तथा आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। प्याज सहित सभी सब्जियां आम आदमी की थाली से गायब हो चुके हैं। अपने पिछले पांच साल के कार्यकाल में 100 दिन में मंहगाई कम करने का वायदा करने वाली मोदी सरकार ने मंहगाई से देश की जनता का छः साल में बुरा हाल कर दिया। 2014 में 450-का रसोई गैस सिलेण्डर 723-पहुंच गया, पेट्रोल 74 रुपये 90 पैसे तथा डीजल 68 रुपये 30 पैसे पहुंच गया। वह भी तब जब कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें लगातार कम होती रही।

फेयरवेल आयोजित

(संवाददाता) देहरादून। आर्यन स्कूल ने कक्षा बारहवीं के निवर्तमान छात्रों के लिए शैलेक्सीर थीम पर फेयरवेल 2019-20 की मेजबानी की।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स, 74/9, आराधर, देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय:
शिवम मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०-
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं०
UTTHIN200515735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।